



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2013/पौष 14, 1934
No. 41] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2013/PAUSA 14, 1934

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2013

का.आ. 42(अ).—वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और भारतीय नौवहन निगम बनाम फारवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया (एफ एस यू आई) तथा अन्य के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका सं. 576 में बंबई स्थित न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए फैसले के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा पोत स्वामियों और एफ एस यू आई ट्रिब्यूनल के बीच निम्नलिखित विवाद के निपटारे के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन करती है :—

(i) क्या इंडियन नैशनल शिपओनर्स एसोसिएशन (आई एन एस ए) और नैशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया (एन यू एस आई) के बीच राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड (एन एम बी) प्लेटफॉर्म पर 24/02/2012 को हुआ समझौता, जिसे एन एम बी प्लेटफॉर्म के अधीन रहने का दावा किया गया है, एफ एस यू आई के सदस्यों सहित सभी कामगारों पर बाध्यकारी होगा।

(ii) यदि हाँ, तो ट्रिब्यूनल द्वारा क्या आदेश किया जाना है ?

(iii) यदि नहीं, तो क्या एफ एस यू आई की दिनांक 28-4-2010 को की गई माँग न्यायोचित और उचित है और क्या उसे मान लिया जाना चाहिए ?

2. श्री एन. एन. कुमार, उपाध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास एकल-सदस्यीय ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करेंगे।

3. यह ट्रिब्यूनल इस मामले का शीघ्र निपटारा करेगा और अपने फैसले की जानकारी केन्द्र सरकार को इस आदेश की अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर देगा।

[फा. सं. सी-18018/6/2012-एम ए]

एन. मुद्गानन्दम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2013

S.O. 42(E).—In exercise of the powers conferred by Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and in pursuance of the Judgment passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Bombay in W.P. No. 576 of 2012 in the matter of Shipping Corporation of India V/s Forward Seamen's Union of India (FSUI) and others, the Central Government hereby constitutes a Tribunal for referring the following dispute between the Ship owners and FSUI:—

(i) whether the settlement dated 24/02/2012 reached between Indian National Ship-owners' Association (INSA) and National Union of Seafarers of India (NUSI) on National Maritime Board (NMB) platform, which is claimed to have been under the NMB platform is binding on all workmen including members of FSUI ?

(ii) if yes, what order is to be made by the Tribunal ?

(iii) if no, whether demands of FSUI dated 28-4-2010 is just and proper and should be granted ?

2. Shri N.N. Kumar, Deputy Chairman, Jawaharlal Nehru Port Trust will function as the single-member tribunal.

3. The tribunal shall dispose of the reference expeditiously and submit its award to the Central Government within 3 months from the date of issue of notification of this Order.

[F.No. C-18018/6/2012-MA]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.